

एकता की राह पर कदम

I. बायलोरूस में संघर्षरत मजदूरों के लिये समर्थन की एक अपील वहाँ से रूसी भाषा में प्रसारित हुई। बर्लिन में उस अपील का जर्मन भाषा में अनुवाद करके उसे प्रसारित किया गया। न्यू यार्क से उस अपील का अंग्रेजी अनुवाद हमें प्राप्त हुआ है।

★विलेयक नगर स्थित जेनिथ फैक्ट्री में वरकरों ने इस वर्ष 12 से 14 जनवरी तक चाणचक्र हड़ताल की। उस हड़ताल में शामिल होने के लिये मैनेजमेन्ट ने 14 मजदूरों पर मुकदमा शुरू कर दिया है।

★ट्रांजिस्टर नाम की फैक्ट्री में मजदूरों ने सरकारी कानूनों पर अमल करवाने के लिये एक दिन एक घन्टे की कानूनी हड़ताल की। इस साल 12 जनवरी को वरकरों की आम सभा हुई और 15 फरवरी को मजदूरों ने विरोध सभा की। इस पर मैनेजमेंट ने एक वरकर को नौकरी से निकाल दिया है।

★इन्टेग्रल इन्डस्ट्रीयल कम्प्लेक्स में जरजिन्सकी फैक्ट्री में 400 वरकरों ने झूटी के दौरान मीटिंग की। अखबार व पर्चे बाँट कर समाचारों-विचारों का आदान-प्रदान करने और संगठित होने के प्रयासों को कुचलने के लिये मैनेजमेंट ने चेतावनियों की झड़ी लगा दी है।

★बेलवार इन्डस्ट्रीयल कम्प्लेक्स में स्ट्राइक कमेटी की अपील और अखबार बाँटने के लिये पुलिस ने एक मजदूर को गिरफ्तार किया। मैनेजमेंट ने एक अन्य वरकर को डिसमिस कर दिया है।

★इस साल जनवरी और फरवरी में मोगिलयोन नगर में आम सभाओं और जलूसों में सक्रिय रहने के लिये सरकारी वकील ने दो मजदूरों पर मुकदमे शुरू कर दिये हैं।

मजदूरों के समर्थन में बायलोरूस सरकार को विरोध-पत्र भेजने का पता है -

The President, Respublika Belarus, Minsk, BELARUS, CIS

II. भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच गुजरात समुद्र तट के सर क्रीक क्षेत्र पर विवाद है। उस क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले भारत सरकार के नागरिक हाथ लगते हैं तो पाकिस्तान सरकार के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और पाकिस्तान सरकार के नागरिक हाथ आते हैं तो भारत सरकार के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। नतीजतन हर समय सैंकड़ों मछुआरे भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार की जेलों में बन्द। कई साल से यह हो रहा है। इधर कुछ समय से संगठित व खुले तौर पर भारत सरकार के नागरिक मछुआरे भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार के नागरिक मछुआरों की गिरफ्तारियों का विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार के नागरिक मछुआरे पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत सरकार के नागरिक मछुआरों की गिरफ्तारियों का विरोध कर रहे हैं। सरकारों द्वारा सीमा रेखायें खींच कर नागरिक और विदेशी के खानों में बाँटे मछुआरे अपने सरकार-विरोधी कदमों की जानकारीयों सीमा के आर-पार एक-दूसरे को दे रहे हैं। इस सिलसिले में मछुआरों ने सरकारों के खिलाफ हड़तालें की हैं।

(अमरीका से प्रकाशित डिस्कशन बुलेटिन के मई-जून 94 अंक में ओमदास-रमेश।)

कम्पीटीशन के गुल

हर साल इंग्लैंड में ही स्तन का कैंसर 15 हजार स्त्रियों की जान लेता है। इसलिये जब यह खोज हुई कि स्तन कैंसर की जड़ क्रोमोजोम 17 में कहीं पर है तो सर्वत्र उत्साह का संचार हुआ। ऐसा लगा कि बीमारी पकड़ में आने ही वाली है।

क्रोमोजोम के जिन हिस्सों को खारिज किया जा सकता है उसके बारे में दुनियाँ-भर में वैज्ञानिकों के दल नियमित रूप से जानकारीयों का आदान-प्रदान करने लगे। इस जानलेवा बीमारी के इलाज के लिये

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निस्वार्थ भाव से मिलजुल कर काम कर रहे वैज्ञानिकों की एक बढ़िया तस्वीर उभरी। लेकिन अब वैसी बात नहीं है।

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की रिसर्च टीम के मुखिया साइमन स्मिथ कहते हैं, "जैसे-जैसे बीमारी की जड़ को पहचानने के निकट पहुँचते गये वैसे-वैसे ग्रुप एक-दूसरे से पर्दा करने लगे। अब रिश्ते टूटने पड़ गये हैं क्योंकि हममें से कोई भी दूसरे को जानकारी देना नहीं चाहता। एक आदर्श विश्व में हम एक-दूसरे से बात

कर रहे होते न कि जानकारी को छिपा रहे होते। लेकिन हमारे काम का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि क्या-कुछ हमारा छपा है। अगर हम दूसरे नम्बर पर होते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती।"

यानि, विजेता को वाहवाही, ढेरों रुपये इनाम और अधिक बजट मिलता है। क्या कम्पीटीशन एक शानदार चीज नहीं है? लाखों महिलाओं और उनके शोक संतप्त परिवारों से यह कहो। (सोशलसिस्ट स्टैंडर्ड, दिसम्बर 93)

इस अंक में

- एस्कोर्ट्स, झालानी, गुडईयर, बाटा
- दिल है के मानता नहीं
- महर्षि आयुर्वेद कारपोरेशन
- वर्कशॉप मजदूर
- रेल यात्रा

डंकल-गैट के समर्थकों और विरोधियों में मार्के की बात पर सहमति है। दोनों मानते हैं कि मजदूरों के वेतन में कमी करना देश के हित में होता है और मजदूरों के वेतन में वृद्धि देश के खिलाफ है। यह सार की बात मजदूरों और देश के बीच क्या रिश्ता दिखलाती है?

कार्ड की हकीकत

जिन्दगी की काल्पनिकता

बहुचर्चित और लोकप्रिय मिस्टर शेषन की एक दिमागी उड़ान भारत सरकार के नागरिकों के लिये जीवन के नये अर्थ लिये है। इसकी एक झलक मनीपुर में मिलने भी लगी है। वहाँ हथियारबन्द दस्ते चुनाव बहिष्कार करवाने के लिए फोटो लगे पहचान-पत्र छीन कर सरकार के कुछ विभागों के लिये हाइ-मॉस के नागरिकों को काल्पनिक बना रहे हैं। जिन्दगी और कार्ड के बीच उलट-पुलट हो रही है। इस पर समाज में बहस क्यों नहीं हो रही?

सरकारी तन्त्र, राजनीतिक पार्टियाँ और मैनेजमेंट आम लोगों की सहमति से उन पर अपना कन्ट्रोल बनाये रखने में अधिकाधिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। ऐसे में बढ़ते पैमाने पर दमन करना जरूरी हो जाता है और ये यह कर रही हैं। दमन के लिये कन्ट्रोल तथा कन्ट्रोल के लिये पहचान निर्धारित करना उपयोगी उपाय हैं।

फोटो लगे पहचान-पत्र सामाजिक समस्याओं के तकनीकी समाधान का एक शास्त्रीय उदाहरण हैं। प्रशासन विशेषज्ञ मिस्टर शेषन की यहाँ इसमें अग्रणी भूमिका है। वैसे, बढ़ता सामाजिक असन्तोष मिस्टर शेषन के संगी-साथियों का हर देश की सरकार में वजन बढ़ा रहा है।

फोटो लगा पहचान-पत्र वास्तव में है क्या? यह एक कार्ड है जो व्यक्ति को उसकी पहचान देगा। इतना ही नहीं, सब फोटो लगे पहचान-पत्रों का रिकार्ड कम्प्यूटरों में होगा जो कि खुफिया पुलिस के कन्ट्रोल में होंगे। किसी के पास कार्ड नहीं होने का मतलब होगा सरकार के लिये उस व्यक्ति का न होना। अगर आप कम्प्यूटर के पर्दे पर खुफिया पुलिसवालों की निगाह में नहीं आयेगे तो आपका अस्तित्व ही नहीं होगा।

लोग इन पहचान-पत्रों के लिये राजी हो रहे हैं। जो नजरअन्दाज किया जा रहा है वह यह तथ्य है कि फोटो लगे पहचान-पत्र व्यक्ति की बची-खुची आजादी को और कम करने के औजार हैं।

मजदूरों द्वारा अपने अनुभवों और विचारों को प्रस्तुत करने के लिये लिखे लेखों और रिपोर्टों को हम इस पन्ने पर छापेंगे। ऐसे लेख और रिपोर्ट हमारे लिये खुशी की चीज हैं। अपनी बात हमें लिख कर दें। आपको अपनी बातें छपवाने के लिये कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे।

रेल यात्रा

10 मई की बात है। हम लोग बल्लबगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँचे। पहले हमने 3 टिकट 453 रुपये में ले लिये। फिर हम में से एक दो टिकट लेने गया जिनकी कीमत 302 रुपये थी। उसने 302 रुपये के बदले टिकट काउंटर पर 350 रु. दिये। टिकट देने वाले ने 2 टिकट दे दिये और बाकी के पैसे रख लिये। चूँकि ट्रेन स्टेशन पर पहुँच गई थी इसलिये उसने पैसा छोड़ना ही मुनासिब समझा। फिर भी दुर्भाग्यवश अत्याधिक भीड़ के कारण हमें 'उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस' छोड़नी पड़ी। गाड़ी छूटने के बाद जब हम लोग 48 रु. मँगाने गये तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने आपका कोई पैसा नहीं लिया है।

उसके बाद हम नई दिल्ली स्टेशन पर 'श्रमजीवी एक्सप्रेस' पकड़ने के लिये गये। जैसा कि हमें ज्ञात है कि इसमें दो जनरल डिब्बे हैं। एक आगे एक पीछे। भीड़ अधिक थी इसलिये कुछ लोग पीछे और कुछ आगे के डिब्बे की ओर बढ़ गये। जब लोग आगे के डिब्बे में बैठ गये तब Defence वालों ने उस डिब्बे के ऊपर अपना Board लगा दिया और सभी लोगों को बेल्ट और झापड़ मार-भार कर उतार दिया। इसमें बहुत लोग बुरी तरह से घायल भी हुये। हम 8 में से जो 5 जा रहे थे उन्हें भी 2-4 बेल्ट लगी। अन्ततः हमने उस गाड़ी को भी छोड़ दिया।

फिर उसके बाद हम लोग पूर्वा एक्सप्रेस पकड़ने के लिये 4 न. प्लेटफार्म पर गये परन्तु वहाँ पर भी अत्याधिक भीड़ एवं जनरल डिब्बों की कमी के कारण गाड़ी पकड़ने में सफल नहीं हो सके।

फिर अन्त में हमने मगध एक्सप्रेस पकड़ने की सोची जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम 7.45 बजे चलती है। गाड़ी अपने नियत समय यानि 7.15 पर प्लेटफार्म नं. 6 पर आ गई। अन्तिम गाड़ी थी इसलिये हम लोगों ने निर्णय किया कि इसमें किसी भी तरह से सवार होना है। अतः हम लोग भी धक्का-मुक्की करके किसी तरह घुसने में सफल हो गये परन्तु दुर्भाग्यवश हम लोगों में से एक का पर्स किसी ने निकाल लिया। इसी बीच दो यात्रियों में ही गाड़ी पर चढ़ने के लिये तकरार हो गई और तकरार में एक लड़के की पीठ में चाकू लग गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। चूँकि इसी भीड़-भाड़ में समय बीत गया और गाड़ी छूटने का समय हो चुका था अतः हम लोगों ने भी वहाँ से जाना ही उचित समझा क्योंकि हम लोगों को भी अभी गाड़ी पकड़ कर फरीदाबाद आना था।

रेल मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिये कि या तो रेलगाड़ी में जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाये या फिर रिजर्वेशन की सुविधा प्रत्येक स्टेशन से की जाये तथा इसकी दर में भी परिवर्तन किया जाये जिससे मध्यम वर्ग के लोग भी आसानी से सफर कर सकें।

23.5.94

- हरिओम चन्द

वर्कशाप मजदूर की कलम से

I. 19 धर्मकाँटा रोड़ मुजेसर, ई.पी. इलेक्ट्रो में 23 मार्च 1994 को एक प्रैस आपरेटर का दाहिना हाथ प्रैस में आ जाने से उसकी तीन अँगुलियाँ जड़ से कट गई और ई एस आई में डॉक्टर ने आधा हाथ काट कर साफ कर दिया। इधर बाकी मजदूर और मालिक लोग 25-26 तारीख को खूब जम कर रंग-गुलाल खेले और रंगरेलियाँ मनाये। अरे साहब लोगो जरा उस बेचारे मजदूर के दिल से तो पूछो कि होली के तीन दिन पहले जिसका एक हाथ कट गया उसके दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन किसको किसी के दुख की चिन्ता है? अपना भला तो जग भला है।

II. धर्मकाँटा रोड़ मुजेसर स्थित के के इंजिनियरिंग को 27-28 साल हो गये और मुजेसर की जानी-मानी वर्कशॉप है। इसमें 30-32 मजदूर कार्यरत हैं। करीब-करीब सब परमानेन्ट हैं। सब का फन्ड, ई एस आई कटती है। लेकिन किसी भी मजदूर को आज तक फन्ड स्लिप नहीं मिली है और न ई एस आई कार्ड मिला है कि जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों का इलाज करवा सके। अगर कार्य करते समय चोट लग जाती है तो प्रायवेट में दवा-पट्टी करा दी जाती है।

के के इंजिनियरिंग का नाम बदल कर अपनी लड़की के नाम आशमा इंजिनियरिंग करने का फैसला किया गया है। अब मजदूरों का फन्ड काटना बन्द कर दिया गया है। कोई ना कोई बहाना बना कर मजदूर निकाले जा रहे हैं। चार महीने के अन्दर चार मजदूर निकाल दिये। निकाले मजदूरों का फन्ड का फार्म भरने से मालिक कतराते हैं। अभी-अभी रमाशंकर टर्नर को 16.5.94 को निकाल दिया गया। चार साल से कार्यरत था। ये कह कर कि जो काम तुमने चार साल किया कोई ठीक नहीं किया अब तू हिसाब ले जा और उसका गेट बन्द कर दिया गया। कितनी तारीफ करने योग्य मालिक है कि चार साल नुकसान बरदास्त किया। ऐसे लोगों की तो चाहे जितनी तारीफ करो कम है।

हिसाब भी अपनी मर्जी का दिया जा रहा है। किसी को 10 दिन तो किसी को 14 या 15 दिन का। लगता है जैसे कि अपने घर का राज और कानून आ गया है कि जब दिल किया कान पकड़ कर गेट बाहर कर दिया।

---- 26.5.94

बाटा

42 साल पुरानी बाटा शू वर्कर्स यूनियन उन कुछ चुनी हुई पुरानी यूनियनों में से है जिसने आजकल की विषम परिस्थितियों में अपना वजूद बनाये रखा है।

फिर भी लाल झंडे के दसूलों के अनुसार अपनी संगठनात्मक छवि जैसी होनी चाहिये वैसी बनाने के प्रयास नहीं किये जा सके क्योंकि केन्द्र, राज्य व फरीदाबाद स्तर पर जो हालत बनाई गई है उसी की कार्बन कापी बनाने की कोशिश रही है। इसका कारण यह है कि जो सक्रियता पहले कम्युनिक्स, पुलिस प्रशासन हरियाणा सरकार और केन्द्र सरकार की कुनीतियों, मजदूर व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ होती थी, अब वह स्तर गिरा दिया गया है।

इधर 4-5 सालों से विश्वव्यापी आर्थिक संकट के दौर ने मजदूरों को अपने पुराने संघर्षों के तरीकों में भी बदलाव करने को मजबूर किया है। वैकल्पिक संघर्षों की नीति स्पष्टतः तय नहीं हुई है क्योंकि नीति निर्धारक कई झंडों में बँटे हुये हैं।

प्रबंधकों के आये दिन की धमकियों, वर्कलोड बढ़ाने की नीतियों, कुप्रशासन व भ्रष्टाचार से मजदूर अधिक चिन्तित हुआ है। केन्द्र व राज्य सरकार की मजदूर विरोधी उद्योग नीति ने तो और भी दमनात्मक रूख अपना लिया है। बेरोजगारी इतनी हो गई है कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधेरे में है।

बाटा मैनेजमेंट ने भी अन्य उद्योगपतियों की भाँति ही अपने हथकंडे और बेशर्मी से बढ़ा दिये हैं। उत्पादन जहाँ 20-20 विभागों से लिया जाता था अब मात्र 6 विभाग रह गये हैं। श्रम शक्ति जहाँ 2200-2400 थी अब लगभग 1000 रह गये हैं। कई जॉब खत्म कर दिये हैं, उन पर नये मजदूर नहीं लगाये जाते हैं, ठेकेदारी बढ़ा दी गई है। जहाँ पहले सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग का काम ठेके पर

होता था, अब सेक्यूरिटी, हेल्पर, कैन्टीन, ब्लैकस्मिथ, कार्टन, सफाई व ट्रान्सपोर्ट भी ठेके पर कर दिये गये हैं। यहाँ तक कि वालेन्ट्री रियारमेंट स्कीम थोपने के लगातार प्रयास व दबाव मैनेजमेंट बनाये हुये है।

कम्पनी को 30 करोड़ का शुद्ध मुनाफा वर्ष 1993-94 में हुआ है परन्तु मजदूरों के लिये कुछ भी आफर नहीं है यद्यपि डिमान्ड नोटिस दिये हुये 10 महीने से ऊपर हो गये हैं। सरकार, लेबर डिपार्टमेंट कुँभकर्णी नींद सोया हुआ है। ऐसे में मजदूरों को संघर्षों के नये तरीके सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले 2.5.94 से 17.5.94 तक (शनिवार रविवार छोड़ कर) क्रमिक भूख हड़ताल पर मजदूर बैठे। मजदूरों ने बेमिसाल एकता का परिचय दिया। यद्यपि भूख हड़ताल 25.4.94 से होनी थी, लीडरशिप ने मैनेजमेंट पर अतिविश्वास किया जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। कम्पनी ने बातचीत का झामा रच कर अपना मकसद पूरा किया। ऐसा इसलिये हुआ कि मजदूरों से विचार-विमर्श नहीं किया गया था। यदि मजदूरों की राय ली जाती तो मजदूर 25.4.94 से ही भूख हड़ताल करने को बाध्य करते। महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब भी लीडरशिप राय लेती है तो मजदूर राह दिखाते हैं परन्तु कई बार ऐसा नहीं किया जाता जिससे पुरानी शान, परम्परा को चोट पहुँचती है।

जहाँ लीडरशिप को नीति तय करने का हक है वहीं मजदूरों को गलत नीति को बदलने की क्षमता, परिपक्वता दिखाते रहना होगा तभी आज की कठिन परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। जब भी ऐसा हुआ है मजदूर विजयी रहे हैं। किसी भी लीडरशिप के अन्ध समर्थकों पर नकेल रख कर बाटा के मजदूरों ने अनेकों बार सफलता के कदम चूमे हैं। 25.5.94 - - बाटा का एक मजदूर

इस अखबार को हम अधिक संख्या में छपना चाहते हैं ताकि बड़ी तादाद में मजदूर इसे पढ़ें और यह अखबार भी अनुभवों तथा विचारों के आदान-प्रदान के लिये एक मंच बने। रुपये-पैसे की कमी हमारे लिये एक बाधा है। अगर आप इस अखबार को उपयोगी समझते हैं तो कृपया आर्थिक योगदान भी दें।

दिल है के मानता नहीं

टी-सीरीज ग्रुप की फैक्ट्रियों में पाँच-छह साल से लगातार काम कर रहे वरकरों ने परमानेन्ट किये जाने की बात की। संसार में आना-जाना लगा रहता है, भला कोई चीज स्थिर है यहाँ? मलेच्छों की ऐसी बेतुकी बात का उत्तर मीन ही है। मिल रहे दस्ताने और गैस मास्क देने बन्द करने पर केमिकल वरकरों ने चक्कर आने और शरीर सूखने की शिकायत की। इस नश्वर संसार में शरीर की सुरक्षा की बात अज्ञानी ही कर सकते हैं! मजदूर यूनिफार्म रोके जाने की बात कर रहे थे? मूठ हैं! अरे चोगे का भी कोई महत्व होता है भला? आत्मा को देखो कैसे यह शरीर-रूपी यूनिफार्म त्यागती रहती है! बोनस? छी-छी, हाथ का मैल है। काहे को माया से मोह करते हो! चाय और भोजन के टाइम में से दस मिनट काट लेने पर मजदूर खुसर-पुसर कर रहे हैं? बस्कर रावस हैं! काल-महाकाल में विचरण करो। वण वणिक् हैं, इनके फेर में पड़ना भटकना है! लेबर डिपार्टमेंट में तारीख? अजी असी तो बस माता दे दरबार किच ही हाजरी देन्दे हन! इस्तीफों के लिये धमकियाँ? देखिये साहब, आधी तो नारियाँ हैं और हमारे शास्त्र-हमारी संस्कृति कहती है, विलकुल ठीक कहती है कि रावस, शुद्र, मलेच्छ और नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी! कानून? ईश्वरीय कानून की बात कीजिये जनाब नहीं तो दफा हो जाइये। आप नहीं जानते मिस्टर कि फैक्ट्रियों के अन्दर वीडियो कैमरों द्वारा श्रूओं की हर पल निगरानी जरूरी है नहीं तो यह रावस उत्पादन बढ़ाने और खर्च में कटौती के राष्ट्रीय यत्न में विघ्न डाल देंगे। जमाने के साथ चलिये श्रीमान नहीं तो कम्प्यूटीजेशन में देश पीछे छूट जायेगा और भारत माता फिर गुलाम हो जायेगी...

माता वैष्णो देवी के परम भगत, फिल्मी दुनियाँ की हस्ती, भक्ति गायिका अनुराधा पौडवाल के बिजनेस पार्टनर और टी-सीरीज ग्रुप के कर्ता-धर्ता गुलशन कुमार की मजदूरों के असन्तोष व आन्दोलन पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया रही है।

टी-सीरीज ग्रुप ने 12 कम्पनियाँ खड़ी की हैं। नोयडा, ग्रेटर नोयडा और बुलन्दशहर जिले स्थित 30 फैक्ट्रियों

में चार-पाँच हजार मजदूर काम करते हैं। नोयडा और बम्बई में फिल्म स्टूडियो हैं। आडियो व वीडियो कैसेट, टेलीविजन, VCP/VCR, टू-इन-वन ही नहीं बल्कि टी-सीरीज की फैक्ट्रियों में वाशिंग पाउडर का भी उत्पादन होता है।

हाजरी कार्ड नहीं देने, पे स्लिप नहीं देने, रजिस्टर तक पर नाम नहीं, पे रोल पर नाम नहीं, एक फैक्ट्री में काम करने वाले को दूसरी फैक्ट्री का कार्ड देने, ट्रान्सफर, कम्पलसरी ओवरटाइम लेकिन उसके लिये पेमेन्ट नहीं (महिलाओं से सुबह 9 बजे से रात साढ़े सात तक और पुरुषों से रात दस बजे तक काम करवाना), बरसों काम करने के बाद भी परमानेन्ट नहीं करना — यह टी-सीरीज ग्रुप की फैक्ट्रियों की एक तस्वीर है। दो साल पूर्व मैनेजमेंट ने साधनों की कमी बता कर 2600 परमानेन्ट मजदूरों के पेच और कसने शुरू किये। बोनस रोक लिया, कैन्टीन बन्द कर दी, यूनिफार्म नहीं दी, केमिकल क्षेत्र में दस्ताने व मास्क देना बन्द, और बोलने पर बिना कारण बताये सस्पेन्ड।

संगठित हो कर जुलाई 93 में वरकरों ने मैनेजमेंट को अपनी डिमाण्डें दी। मैनेजमेंट ने उत्तर नहीं दिया। नवम्बर 93 में रिमाइन्डर। जवाब में मैनेजमेंट ने गोपाल सोप इन्डस्ट्रीज में तालाबन्दी कर दी। दो दिन बाद आलोक तथा रजनी इन्डस्ट्रीज भी बन्द कर दी और 38 वरकर सस्पेन्ड कर दिये। लेबर डिपार्टमेंट में तारीखों पर मैनेजमेंट कभी भी उपस्थित नहीं हुई। अलग से वरकरों से एक समझौता किया पर उस पर अमल नहीं किया। मजदूरों की नोयडा फिल्म सिटी आफिस पर भूख हड़ताल। इस साल जनवरी में तीन और फैक्ट्रियों में तालाबन्दी। 12 यूनिटों में प्रोडक्शन बन्द करने के बाद 14 मार्च को मजदूरों ने टी-सीरीज की सब फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी।

28 मार्च को एग्रीमेंट। अखबारों से मजदूरों को पता चला। साइन करके लीडर गायब। एग्रीमेंट में क्या है इसकी जानकारी वरकरों को आज तक नहीं है। मैनेजमेंट के अनुसार मुनाफा नहीं होने तक वेतन वृद्धि नहीं, चाय व भोजन के समय में कटौती, आधे सस्पेन्ड वरकर इयूटी पर लेना, वॉलेन्ट्री रिटायरमेंट स्कीम। बाद में फिल्मी

स्टाइल में कन्वे उचका कर गुलशन कुमार ने कहा, “वह कोई एग्रीमेंट नहीं थी। दरअसल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये चाय और भोजन के समय में दस मिनट की कटौती की गई है।”

टी-सीरीज मैनेजमेंट के बारे में 1987 में काम कर रही एक वरकर कहती है, “हमें धमकियाँ दी गई कि हमने इस्तीफे नहीं दिये तो हमारे चेहरे दिगड़ देंगे और डी टी सी बसों में हमारी गन्दी नन्दें चिपकवा देंगे।”

हड़ताल के बाद टी-सीरीज ग्रुप की फैक्ट्रियों में हालात के बारे में सुपर कैसेट्स का एक वरकर कहता है, “मैनेजमेंट ऐसे हालात बना रही है कि हम नन्द इस्तीफे दे कर चले जायें ताकि वह नई भर्ती कर सके। पहले दो वरकर एक मशीन चलाने थे जबकि अब एक को दो मशीनें चलानी पड़नी हैं और आसमान छू रहा प्रोडक्शन टारगेट पूरा करना पड़ता है। थक जाने पर बैठने के लिये जो स्टूल थे वह हटा दिये गये हैं और अब सारे समय समय खड़े रहना पड़ता है। न तो चाय दी जाती है और न चट के लिये समय दिया जाता है। छह से दो घण्टे शिफ्ट में लन्च टाइम भी नहीं है। फैक्ट्री में वीडियो कैमरे लगा दिये गये हैं। आपस में बात करना तो दूर, वरकर एक-दूसरे की ओर देख कर मुस्करा भी नहीं सकते। कल ही एक वरकर को मुस्कुराने-भर के लिये टर्निंग लैटर पकड़ा दिया गया। टायलेट जाना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि वहाँ भी वीडियो कैमरे लगा दिये गये हैं।”

और फैक्ट्री में वीडियो कैमरे लगाने के बारे में भक्ति गीतों से शक्ति बटोरने वाला गुलशन कुमार कहता है, “यह करना पड़ा है क्योंकि काम में बचने के लिये मजदूर घन्टों बाथरूम में छिपे रहते थे।”

(जानकारी राष्ट्रीय सहारा मैगजीन के मई 94 अंक से ली है।)

बयानों की भूल भुलैया

शुक्रवार, 13 मई की रात को दिल्ली कैन्ट में बरार स्क्वायर के निकट फौजियों ने 200 झुगियों के निवासियों को खदेड़ कर झुगियों में आग लगा दी। शनिवार रात को फौज के प्रवक्ता ने कहा, “सैन्य क्षेत्र में अनधिकृत कब्जे सुरक्षा कारणों से फौरन हटा दिये जाते हैं।”

दिल्ली फायर सर्विस ने कहा कि शुक्रवार रात को 9 बजे के करीब फोन पर इमरजेंसी सूचना मिलते ही दिल्ली कैन्ट में आग बुझाने वाली तीन गाड़ियाँ भेजी।

आरम्भ में पुलिस ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि “कोई झगड़ा-झंझट नहीं हुआ। फौज के सिपाही कुछ पुराना रिकार्ड जला रहे थे और पुलिस को झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती में आग लगी होने की कुछ झूठी फोन काल मिली थी।”

दिल्ली फायर सर्विस ने कहा कि सात दिन से झुगियों तोड़ने का अभियान चल रहा था और फौज झुगियों के कबाड़े को आग लगा रही थी।

फिर सम्पर्क करने पर क्षेत्र की पुलिस चौकी के इनचार्ज ने कहा, “वह पुराने रिकार्ड नहीं थे। झुगियों को जलाया जा रहा था पर कोई झगड़ा-झंझट नहीं

हुआ था। यह झुगियाँ फौज द्वारा खाली करवा ली गई थी और उनमें कोई नहीं रह रहा था। मौके पर सी आर पी और फौज के सिपाही मौजूद थे। झुगियाँ अनधिकृत तौर पर बनाई गई थी।”

यह बताते हुये कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, दिल्ली कैन्ट के एरिया कमान्डर ब्रिगेडियर ने कहा, “हम सैन्य क्षेत्रों से अनधिकृत कब्जों को वास्तव में हटाते हैं पर मुझे इस वाक्य की कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ बरार स्क्वायर के निकट की किसी झुग्गी को छूआ तक नहीं गया है। किसी को बेघर नहीं किया गया है। यह आरोप बिलकुल झूठे हैं।”

एक अन्य फौजी ने कहा, “झुगियों में रहने वालों को कुछ दिन पहले इलाका खाली करने को कहा गया था। सैन्य क्षेत्र में जनता को रहने की हम इजाजत नहीं दे सकते। सूचना के बाद झुगियाँ तोड़ी हैं। किसी के जल जाने का खतरा नहीं था।”

(25 मई के पायनियर अखबार की सामग्री।)

फरीदाबाद में मजदूरों के सामुहिक कदम

(फैक्ट्रियों में तथा बस्तियों में सामुहिक कदमों की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाना हमारे लिये बुझी का काम है। अगर आपके पास ऐसी जानकारी है तो वह हमें दें।)

★ **एस्कोर्ट्स हीरियों प्लान्ट** में यह समझौता था कि अपने साधनों से आने वाले वरकर दिल्ली से फैक्ट्री बसों के पहुँचने तक बेरोकटोक आ सकते थे। हाल की एग्रीमेंट के बाद मैनेजमेंट ने आठ के बाद इन वरकरों के नाम नोट करने शुरू कर दिये हालांकि बसें फस्ट प्लान्ट आदि हो कर सवा आठ के करीब ही पहुँचती हैं। इस पर दस मई को आठ बजने से पहले पहुँचे वरकर गेट पर रुकते गये और पैदल-साइकिल- स्कूटर- मोटरसाइकिलों वाले मजदूरों की गेट पर भीड़ लग गई। सवा आठ बजे बसों के पहुँचने के बाद सब वरकर इक्वेटे फैक्ट्री में जाने लगे। मैनेजमेंट ने मेन गेट बन्द कर दिया। साइड के छोटे गेट से साइकिलों-स्कूटरों-मोटरसाइकिलों के साथ प्रवेश में मजदूरों को काफी दिक्कत होने लगी। तब अन्दर पहुँचे वरकर भी लौट कर गेट पर आ गये और उन्होंने मेन गेट खोलने की डिमांड की। माहौल देख कर मैनेजमेंट ने चुपचाप मेन गेट खोल दिया। तबसे एस्कोर्ट्स हीरिया में वह नाम नोट करना बन्द हो गया।

★ **पलवल साइड** से एस्कोर्ट्स में हर रोज एक हजार मजदूर आते हैं। गाँव से सवेरे साइकिल पर पाँच-सात किलोमीटर चल कर पलवल से ट्रेन पकड़ना, पौन घन्टे की रेलयात्रा, स्टेशन से फैक्ट्री की ओर

तेज रफ्तार डेली अप डाउन वालों की रोज की जिन्दगी है। आठ नहीं, ड्यूटी 13-14 घन्टों की पड़ती है। इससे दो मिनट फुरसत की चाह और काम दूसरों पर टालने की लालसा तथा खुरदरापन-अक्खड़पन बहुत बढ़ जाते हैं। अन्य वरकर इन वजहों से इन वरकरों से अक्सर खार खाने लगते हैं।

पैसे बचाने के लिए एस्कोर्ट्स मैनेजमेंट ने पलवल साइड के वरकरों के लिये बसों की व्यवस्था नहीं की है। हाँ, पूरा प्रोडक्शन देने की शर्त पर मैनेजमेंट इन वरकरों को आठ के बजाय साढ़े आठ तक आने देती थी। हाल की एग्रीमेंट में वर्क लोड बढ़ाने के साथ ही मैनेजमेंट ने यह थोड़ी-सी छूट खत्म कर दी। आठ के बाद पहुँचते पलवल साइड के वरकरों को गेटों से लौटाना शुरू कर दिया। मजदूरों का गुस्सा भड़का। दस मई को ट्रेनों से उतर कर एस्कोर्ट्स वरकर प्लान्टों की तरफ भागने की बजाय इक्वेटे हुये और यूनियन दफ्तर पहुँचे। इस सामुहिक विस्फोट से लीडर घबरा गये। यूनियन आफिस को ताला लगा कर वे भाग गये। मजदूरों ने यूनियन दफ्तर पर धरना शुरू कर दिया। लीडरों ने मजदूरों के कदम को गुन्हागर्दी कहा। धरने के खिलाफ लीडरों ने पर्चे छपवाये। मजदूरों के विभिन्न समूहों के बीच फूट डालने के लिये गड़े मुर्दे उखाड़े गये और बबूल के नये बीज बोये गये। 'मजदूर मोर्चा' के अनुसार यूनियन दफ्तर की यह तालाबन्दी मैनेजमेंटों की लॉकआउट जैसी ही थी।

11 मई को भी ट्रेनों से उतर कर एस्कोर्ट्स के पलवल साइड के वरकर

फैक्ट्रियों में जाने की बजाय तालाबन्दी यूनियन दफ्तर पर धरने पर बैठे। यह सिलसिला जारी रहने पर मैनेजमेंट-यूनियन ने मामले पर विचार करने और तब तक साढ़े आठ तक आने की पुरानी स्थिति बरकरार रखने की घोषणा करके यूनियन दफ्तर से मजदूरों का धरना उठवाया। यूनियन दफ्तर की तालाबन्दी खत्म हुई।

★ **भालानी टूल्स** के प्लान्टों में गन्दगी और धूल-धुँआ इस कदर हैं कि वरकर गेट से निकलने को बेचैन रहते हैं। लन्च के समय अधिकतर वरकर फैक्ट्री गेट के बाहर जाते हैं। एक दिन लन्च टाइम खत्म होने के दो-चार मिनट बाद गेट के अन्दर जाते फस्ट प्लान्ट के कुछ वरकरों के नाम मैनेजमेंट ने नोट किये। अगले दिन लन्च के समय फस्ट प्लान्ट के उस शिफ्ट के सब वरकर गेट के बाहर गये और लन्च टाइम खत्म होने के पाँच-सात मिनट बाद इक्वेटे गेट के अन्दर आये। मैनेजमेंट ने नाम नोट नहीं किये और आगे से वह हरकत बन्द कर दी।

★ **गुडईयर** मैनेजमेंट ने छोटी-छोटी बात पर वरकरों को सस्पेंड करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। 9 मई को भी मजदूर सस्पेंड किये गये। इस पर ड्यूटी के समय मजदूरों ने खुद तय किया कि सस्पेंड वरकरों की जगह कोई भी ओवरटाइम नहीं करेगा। मजदूरों के सामुहिक कदम ने गुडईयर मैनेजमेंट के लिये परेशानी खड़ी कर दी।

★ **बाटा फैक्ट्री** की पावर शू डिपार्टमेंट के मजदूरों ने 25 मई को डिपार्टमेंट इन्चार्ज को खराब मैटेरियल

दिखाया और कहा कि इस वजह से जूतों की शोप बिगड़ रही है जिसके लिये मैनेजमेंट बाद में वरकरों की तनखा काटेगी। इस पर डिपार्टमेंट इन्चार्ज ने वरकरों को डाँटा और काम ठीक से करने को कहा। काम भी करो, पैसे भी कटवाओ और धमकियाँ भी झेलो - पावर वरकरों के साथ-साथ अन्य डिपार्टमेंटों के मजदूरों में भी रोष फैला। देखते ही देखते वरकरों ने पूरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बन्द कर दिया। अन्ततः बाटा मैनेजमेंट को अपने अपसर के व्यवहार के लिये माफी माँगनी पड़ी।

★ **एस्कोर्ट्स फस्ट प्लान्ट** में भी एग्रीमेंट के बाद मैनेजमेंट ने एक-एक सैकेन्ड के लिये मजदूरों को तंग करना शुरू कर दिया। इस पर एक दिन साढ़े चार बजे शिफ्ट छूटने पर मजदूरों ने कदम उठाया। किसी भी वरकर ने स्टैन्ड से अपनी साइकिल या स्कूटर नहीं उठाई और सब मजदूर वरकर गेट पर इक्वेटे हो गये। गेट जाम हो गया। साढ़े चार की शिफ्ट वाले वरकर अन्दर नहीं जा सके और गेट के दोनों तरफ भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने आ कर जब मजदूरों से जाम खत्म करने को कहा तब वरकरों ने उन्हें ऐसी खरी-खरी सुनाई कि वे दुम दबा कर चलते बने। एक घन्टे गेट जाम रहा और इससे फैक्ट्री की मशीनें भी बन्द रही। अगले दिन से मैनेजमेंट ने ड्यूटी आने और छूट कर जाने के लिये अलग-अलग गेट कर दिये।

महर्षि आयुर्वेद कारपोरेशन

जगह की कमी के कारण हम महर्षि आयुर्वेद के मजदूरों का पत्र और कविता इस अंक में देने में असमर्थ हैं। संक्षेप में -

23 अप्रैल को कार्ड पंच करके वरकर फैक्ट्री में दाखिल हुये तब मैनेजमेंट ने उन्हें कुछ सादे और कुछ प्रिन्टेड कागजों पर दस्तखत करने को कहा। साइन करने से इनकार करने पर सब वरकरों को गेट बाहर कर दिया गया। 24 का सन्डे था, 25 अप्रैल को मजदूरों का जलूस लेबर डिपार्टमेंट गया और वहाँ प्रदर्शन किया तब मैनेजमेंट सब वरकरों को काम पर

लेने को राजी हुई। लेकिन 5 मजदूरों को ट्रांसफर के नाम पर ड्यूटी पर नहीं लिया और 27 मई तक उन्हें ट्रांसफर लैटर भी नहीं दिया था। वैसे, मैनेजमेंट ने किसी वरकर को नियुक्ति-पत्र नहीं दिया है और जहाँ ट्रांसफर की बात की है वहाँ महर्षि की कोई फैक्ट्री नहीं है।

जबरन इस्तीफे के लिये महर्षि मैनेजमेंट ने 7 मई को दो वरकरों का गेट रोक दिया। विरोध के बाद उन्हें 21 को ड्यूटी पर लिया। और 21 मई को ही सात मजदूरों को फैक्ट्री से सूरजकुंड थाने

ले जा कर पिटवाया गया तथा पुलिस ने उनसे एक कागज पर दस्तखत करवाये जिस पर लिखा था कि नारे नहीं लगायेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, टूल डाउन नहीं करेंगे, भाषण नहीं करेंगे। मैनेजमेंट ने एक वरकर के रिश्तेदार को 24 मई को बदरपुर थाने में बन्द करवाया। महर्षि आयुर्वेद के सब वरकरों को निकालने के लिये मैनेजमेंट महर्षिनगर से 65 लोगों को रोज बस में लाती-ले जाती है।

मई अंक जब बाटा फैक्ट्री गेट पर बँट रहा था उस समय यूनियन प्रधान और कुछ अन्य लोगों ने हमें गालियाँ और धमकियाँ दी। उन्होंने इस अखबार को मैनेजमेंटों का अखबार कहा। उन्होंने इसे अमरीका-परस्त अखबार कहा। इस अखबार में वाकई ऐसी सामग्री होती है क्या? अगर नहीं तो ऐसी प्रतिक्रियायें कौन व्यक्त करते हैं? वैसे, बेहतर होगा अगर हमें यह बताया जाये कि इस अखबार में क्या कमियाँ हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाये तथा अखबार को मजदूरों के लिये बेहतर कैसे बनाया जाये।

जो चाहते हैं कि यह अखबार ज्यादा लोग पढ़ें, ऐसे 150 मजदूर अगर हर महीने दस-दस रुपये दें तो इस अखबार की पाँच हजार की जगह दस हजार प्रतियाँ फ्री बँट सकेंगी।

फरीदाबाद में

● आटोपिन में 8 मई को

नाइट शिफ्ट का वरकर जयनाथ प्रोडक्शन टारगेट पूरा करने के लिये मशीन को चालू रखने के साथ-साथ भट्टी का टेम्परेचर भी देख रहा था। मशीन पर सेपटी नैट नहीं था। सुबह सात-सवा सात भट्टी की ओर मुड़ते वक्त जयनाथ का हाथ मशीन में आ गया। फैक्ट्री में ही तत्काल उसकी मृत्यु हो गई।

■ **नार्दन इंडिया आयरन एन्ड स्टील**, 20/3 मथुरा रोड में मैनेजमेंट ने 21 मई को 45 दिन के लिये ले आफ कर दी। मजदूरों के विरोध के बावजूद हरियाणा सरकार ने फैक्ट्री में ले आफ की इजाजत दी है।

● 19 जून को सुबह दस बजे, 20 को शाम 5 बजे और 21 जून को रात 8 बजे इस अखबार के जून अंक पर मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी में चर्चा होगी। हर कोई इसमें भाग ले सकता है।